

शहरी नियोजन सुधार: नीति आयोग

प्रलिमि्स के लिये:

भारत की जनगणना 2011, सकल घरेलू उत्पाद, शहरीकरण

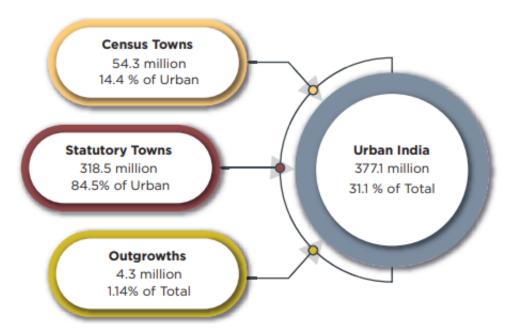
मेन्स के लयि:

भारत में शहरीकरण की वर्तमान स्थिति तिथा शहरी विकास से संबंधित योजनाएँ/कार्यक्रम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नीति आयोग ने 'भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार' (Reforms in Urban Planning Capacity in India) शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है।

Composition of Urban Population



//

प्रमुख बदु

- भारत में शहरीकरण:
 - ॰ शहरीकरण स्तर (राष्ट्रीय):
 - 31.1% (भारत की जनगणना 2011) शहरीकरण स्तर के साथ, वर्ष 2011 में भारत की शहरी जनसंख्या 1210 मलियिन थी।
 शहरीकरण कस्बों (Towns) और शहरों (Cities) में रहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि की संदर्भित करता है।
 - पूरे देश में शहरी केंद्रों (Urban centres) का वितरण और शहरीकरण (Urbanisation) की गति एक समान नहीं है।
 - ॰ देश की 75% से अधिक शहरी जनसंख्या 10 राज्यों- महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमलिनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र

प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और केरल में विद्यमान है।

- राज्यवार परदिृश्य:
 - राष्ट्रीय औसत से ऊपर: गोवा, तमलिनाडु, केरल, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में शहरीकरण का स्तर 40% से अधिक है।
 - राषटरीय औसत से नीचे: बिहार, ओडिशा, असम और उततर परदेश में शहरीकरण का सतर राषटरीय औसत (31.1%) से कम है।
 - केंद्रशासित प्रदेश: दिल्ली, दमन और दीव, चंडीगढ़ तथा लक्षद्वीप में शहरीकरण का स्तर 75% से अधिक है।
- शहरी नियोजन क्षमता में सुधार की आवश्यकता:
 - ॰ बढ़ता शहरीकरण: भारत की शहरी जनसंख्या वशिव जनसंख्या का 11% है।
 - हालॉॅंकि, निरिपेक्ष संख्या (Absolute Numbers) से, भारत में शहरी जनसंख्या संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, पश्चिमी यूरोप और दक्षिण अमेरिका जैसे अत्यधिक शहरीकृत देशों/क्षेत्रों से अधिक है।
 - वर्ष 2011से 2036 के दौरान,भारत में कुल जनसंख्या में 73% वृद्धि के लिये शहरी विकास ही जिम्मेदार होगा।
 - ॰ भारतीय अरथव्यवस्था का केंद्र: शहरीकरण भारत के सकल घरेलू उतुपाद (GDP) में लगभग 60% का योगदान देता है।
 - हालाँकि भारत में बड़े पैमाने पर अपर्यापत अर्थव्यवस्था का स्तर मौजूद है।
 - ॰ भारत के राष्ट्रीय विकास लक्ष्य:
 - आर्थिक विकास लक्ष्य: वर्ष 2024 तक 5 टरिलियन डॉलर अरथवयवसथा।
 - रोज़गार लक्ष्य: वर्ष 2030 तक कुल कार्यबल 0.64 बलियिन होने का अनुमान है, जिसमें से 0.26 बलियिन शहरी क्षेत्रों में कार्यरत होंगे।
 - **बुनियादी अवसंरचना लक्ष्य: <u>राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम</u> के हिस्से के रूप में 11 बड़े औद्योगिक गलियारों का निर्माण, कई मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण।**
 - पर्यावरण संरक्षण लक्ष्य: नदी का कायाकलप, शहरों में सुवच्छ वायु आदि।
 - ॰ **राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP): NIP** के अंतर्गत शहरी क्षेत्र का महत्त्वपूर्ण हस्सि (17%) शामलि है।
 - NIP वर्ष 2020-25 की अवधि के दौरान 111 लाख करोड़ रुपए के अनुमानित निवश के साथ देश में बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं की सुविधा प्रदान करता है।
 - भारत की वैश्विक प्रतिबद्धताएँ:
 - SDG (लकषय 11): सतत विकास को प्राप्त करने के लिये अनुशंसित <mark>तरीकों में से एक के रुप</mark> में शहरी <mark>नि</mark>योजन को बढ़ावा देना।
 - यूएन-हैबटिट का नया शहरी एजेंडा: इसे वर्ष 2016 में हैबटिट-III में अपनाया गया था। यह शहरी क्षेत्रों के नियोजन, निर्माण, विकास, प्रबंधन और सुधार के सिद्धांतों को प्रदर्शित करता है।
 - यूएन-हैबटिट (2020) यह एक अवधारणा के रूप में स्थानिक स्थिरिता का उल्लेख करता है। यह सुझाव देता है कि किसी शहर की स्थानिक स्थितियाँ सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मूल्य तथा कल्याण उत्पन्न करने के लिये अपनी क्षमता को बढ़ा सकती हैं।
 - <u>पेरिस समझौता</u>: भारत के <u>राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (NDC)</u> में वर्<mark>ष</mark> 2005 के स्तर से वर्ष 2030 तक देश के**सकल घरेलू उत्पाद** की उत्सर्जन तीव्रता को 33% से 35% तक कम करने के लक्ष्य शामिल हैं।

सिफारशिं:

- **स्वस्थ शहरों की योजना:** रिपोर्ट में 5 वर्ष की अवधि के लिये '500 **स्वस्थ शहर कार्यक्रम (500 Healthy Cities Programme)'** नामक केंद्रीय क्षेत्र की योजना की भी सिफारिश की गई है। इसके अंतर्गत राज्यों और स्थानीय निकायों द्वारा संयुक्त रूप से पराथमिक शहरों और कसबों का चयन किया जाएगा।
 - इस कार्यक्रम से शहरी भूमि का इष्टतम उपयोग भी हो सकता है।
- ॰ **शहरी शासन को पुनर्स्पष्ट करना:** अधिक संस्थागत स्पष्टता और बहु-अनुशासनात्मक विशेषज्ञता के माध्यम से शहरी चुनौतियों को हल करना।
 - राज्य स्तर पर एक शीर्ष समिति के गठन की सिफारिश की गई है ताकि योजना, कानूनों (नगर और देश नियोजन संबंधी या शहरी और क्षेतरीय विकास अधिनियम, अनय परासंगिक अधिनियमों सहित) की नियमित समीकिषा की जा सके।
- निजी क्षेत्र की भूमिका को सुदृढ़ बनाना: इसके अंतर्गत तकनीकी परामर्श सेवाओं की खरीद हेतु उचित प्रक्रियाओं को अपनाना,
 सार्वजनिक क्षेत्र में परियोजना संरचना और प्रबंधन कौशल को मज़बूत करना तथा निजी क्षेत्र के परामर्शियों को शामिल करना है।
- े मानव संसाधन को सुदृढ़ करने और मांग-आपूर्ति संतुलन के लिये उपाय: भारत सरकार के एक सांविधिक निकाय के रूप में 'राष्ट्रीय नगर और गुराम योजनाकारों की परिषद' का गठन।
 - साथ ही आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) के 'नेशनल अर्बन इनोवेशन स्टैक' के भीतर एक 'नेशनल डिजिटिल प्लेटफॉर्म ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानर्स' बनाने का सुझाव दिया गया है।
- शहरी नियोजन के रहस्योद्घाटन के लिये 'सिटीज़न आउटरीच अभियान'।
- शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाना।

शहरी विकास से संबंधित योजनाएँ/कार्यक्रम

- समार्ट सिटीज: इसका उद्देश्य ऐसे शहरों को बढ़ावा देना है जो मुख्य बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराएँ और अपने नागरिकों को एक गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करे तथा एक स्वच्छ और टिकाऊ पर्यावरण एवं 'स्मार्ट' समाधानों के प्रयोग का अवसर दें।
- अमृत मशिन: इसका उद्देश्य यह सुनशि्चति करना है कि हर घर में पानी की आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन के साथ नल की व्यवस्था हो।
- स्वच्छ भारत मिशन-शहरी: इसका उद्देश्य शहरी भारत को खुले में शौच से मुक्त करना तथा देश में 4041 वैधानिक कस्बे में नगरीय ठोस अपशिष्ट का शत-प्रतिशित वैज्ञानिक प्रबंधन सुनिश्चित करना है ।

- हृदय योजनाः राष्ट्रीय विरासत शहर विकास एवं वृद्धि योजना (हृदय) का लक्ष्य शहरी नियोजन, आर्थिक विकास तथा विरासत संरक्षण को एक समावेशी तरीके और शहर की विरासत को संरक्षित करने के उद्देश्य से एकीकृत करना है।
 प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरीः इस योजना का लक्ष्य पात्र शहरी गरीबों (झुग्गीवासी सहित) को पक्के घर उपलब्ध कराना है।

स्रोत: पी. आई. बी.

